



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2008/वैशाख 1, 1930

No. 148]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2008/VAISAKHA 1, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2008

अंतिम जांच परिणाम

विषय : रूस तथा चीन जन. गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फेरो सिलिकॉन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/19/2005-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत रूस तथा चीन जन. गणराज्य से फेरो सिलिकॉन के आयातों के कथित पाटन के बारे में दिनांक 24-12-2007 की अधिसूचना के तहत निर्णायक समीक्षा आरंभ की थी । निर्णायक समीक्षा संबंधी जांच की शुरुआत घरेलू उद्योग, मै. इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लि., भुवनेश्वर द्वारा दायर की गई याचिका के संबंध में दिनांक 1-11-2007 के निर्णय के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर की गई थी ।

2. मामले की पृष्ठभूमि यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के तहत रूस तथा चीन जन. गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फेरो सिलिकॉन के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच आरंभ करने का निर्णय लिया था । तदुपरांत संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव के निर्धारण के लिए दिनांक 5 जून, 2000 को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी । प्राथमिक जांच के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 16 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. 28/1/2000-डीजीएडी के तहत एक जन सूचना जारी की जिसमें संबद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयात पर अनंतिम शुल्क लागू किया गया था । संबद्ध वस्तु पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. 152/2000-सीमाशुल्क के तहत जारी किया गया । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 28 मई, 2001 को अंतिम परिणाम घोषित किए और प्रति मीट्रिक टन आयात के पहुँच मूल्य (अंतिम परिणाम के पैरा 9 के कॉलम 3 में यथाउल्लिखित) और 764 अम. डा. के बीच के अंतर के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की । भारत सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 25 जून, 2001 की अधिसूचना सं. 67/2001-सीमाशुल्क के तहत लागू किया गया था । यह पाटनरोधी शुल्क अनंतिम शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए लागू किया गया था । अतः यह शुल्क दिनांक 25 दिसम्बर, 2005 तक लागू था ।

3. पाटनरोधी शुल्क लागू करने के चार वर्षों की समाप्ति पर घरेलू उद्योग को इस आशय का चेतावनी पत्र भेजा था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात का पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या इस

मामले में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं और उनसे संबंधित देशों से आयातों की मात्रा तथा पाटन, यदि कोई हो, से संबंधित प्रमाण और इस मामले में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के प्रभाव से संबंधित पूरी जानकारी देने का अनुरोध किया गया था।

4. तत्पश्चात् घरेलू उद्योग (मै. इंडियन मेटल्स एंड फ़ैरो एलॉयज लि. एंड मै. वी बी सी फ़ैरो एलॉयज) ने उपर्युक्त विषय पर निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए याचिका दायर की। मामले की जांच की गई और विस्तृत जांच के बाद संबद्ध देशों से आयात पर फ़ैरो सिलिकॉन पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा न करना उचित समझा गया। तदनुसार डीजीएडी के दिनांक 21.12.2005 के पत्र के तहत आवेदक को सूचित कर दिया गया।

5. दिनांक 21 दिसंबर, 2005 के पत्र से असंतुष्ट आवेदक ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में 2005 की रिट याचिका सी डब्ल्यू सं. 24646 पेश की और यह प्रार्थना की गई कि दिनांक 21.12.2005 के आदेश को खारिज कर दिया जाए क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा करने के लिए बाध्य हैं और केन्द्र सरकार उसके बाद उस संबंध में निर्णय ले सकती है। माननीय न्यायालय ने केन्द्र सरकार को मामले पर विचार करने और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के औचित्य की जांच करने का आदेश दिया।

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार (राजस्व विभाग) द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के औचित्य की जांच की गई। केंद्र सरकार का निर्णय दिनांक 20 जुलाई, 2006 के पत्र के तहत सूचित कर दिया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा न करने का निर्दिष्ट प्राधिकारी का पिछला निर्णय सही है और इसके विपरीत निर्णय लेने के लिए कोई सुदृढ़ आधार नहीं है। अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रूस तथा चीन जन. गणराज्य से फ़ैरो सिलिकॉन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने हेतु समीक्षा अपेक्षित नहीं है।

7. याचिकाकर्ता ने दिनांक 20 जुलाई, 2006 के आदेश को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 13 नवंबर, 2006 को दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी(सी) सं. 16893/2006 के तहत पुनः एक रिट याचिका दायर की।

माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 1.11.2007 के निर्णय में कहा कि :

- (क) निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है और इसके विपरीत प्रतिवादियों के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।
- (ख) निर्णायक समीक्षा नियमावली के नियम 23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी अपेक्षित है।
- (ग) केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2006 को दिया गया आदेश खारिज किए जाने योग्य है और हम ऐसा करते हैं।

उपर्युक्त निष्कर्ष तथा प्रदान की गई राहत के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में निर्णायक समीक्षा हेतु याचिकाकर्ता के अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निदेश दिया। माननीय न्यायालय ने प्रतिवादियों हेतु कोई निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की लेकिन स्वाभाविक रूप से उनसे यथाशीघ्र ऐसा करने की अपेक्षा है।

8. माननीय न्यायालय ने यह निदेश भी दिया कि निर्णय की तारीख से दो माह पश्चात अर्थात् 1 जनवरी, 2008 से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिवादियों द्वारा रूस तथा चीन जन. गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फैंरो सिलिकॉन के सभी आयातों की अनंतिम आधार पर निकासी निर्णायक समीक्षा पूरी होने तथा अंतिम निर्णय लिए जाने तक कर दी गई है।

9. उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (2) के अनुसार प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा हेतु दिनांक 24.12.2007 की जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रति संबंधित माने जाने वाले उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, उद्योग जगत के सहयोगियों, संबंधित देशों के दूतावासों और याचिकाकर्ता को अग्रेषित की तथा उन्हें लिखित में अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दिया। अधिक प्रचार हेतु जांच शुरुआत हेतु सूचना की प्रतियाँ फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, आदि को भी भेजी गई।

(क) प्राधिकारी ने संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों से निम्नलिखित संबंधित निर्यातकों को प्रश्नावली प्रेषित की थी :

- i) चाइना हान्टोनिन्द लि. जियांग्सू- चीन
- ii) नान्जिंग सं. 3 फैंरो एलॉय प्लांट, जियांग्सू
- iii) टियान्जिंग नॉन फ़ैरस मेटल्स-चीन
- iv) हुनाओ फैंरो एलॉय प्लांट- चीन
- v) जिन्चुआन नोनो फ़ैरस मेटल्स कं.- चीन
- vi) जिन्झोउ फैंरो एलॉय प्लांट- चीन
- vii) नान्जिंग फैंरो एलॉय प्लांट- चीन
- viii) जाइबर फैंरो एलॉय वर्क्स- चीन
- ix) जिन्चू आयरन एंड स्टील वर्क्स- चीन
- x) जिशुई कंट्री फ़ैरो सिलिकॉन प्लांट, हुबेई-चीन
- xi) जुन्यी फ़ैरो अलॉय प्लांट गुइजोऊ प्रोविंस- चीन
- xii) चेल्पाबिन्स्क इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल इंटिग्रेटेड प्लांट- रूस
- xiii) क्लचर्स फ़ैरो प्लांट- रूस

(ख) आयातक प्रश्नावली के साथ जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित आयातकों को भी भेजी गई थी :-

- i) ओपीआर के फैंरो एलॉयज लि., नई दिल्ली
- ii) ईएसएसईएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लि., कोलकाता
- iii) मेटलिक एलॉयज, नई दिल्ली
- iv) दुर्गा केमिकल एजेंसी, लुधियाना

- v) हिमानी फेरो एलॉयज लि., नई दिल्ली
- vi) ब्रिटिश मेटल कार्पो. (आई) प्रा. लि.
- vii) मेटको मार्केटिंग इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली
- viii) ओसवाल मिनरल्स, बंगलौर
- ix) मनोहर मानक एलॉय प्रा. लि., मुम्बई
- x) श्रीराम इंटरप्राइजेज चेन्नई
- xi) स्टर्लिंग फेरो एलॉयज प्रा. लि., वडोदरा
- xii) कोठारी मेटल्स लि., कोलकाता
- xiii) श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एलॉय बंगलौर

10. सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 2.01.2008 के पत्र को जारी करने की तारीख से 40 दिनों के भीतर विहित प्रश्नावली में संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी संबंधितों अर्थात् घरेलू उद्योग, निर्यातक एवं आयातक आदि से अनुरोध करते हुए दिनांक 24.12.2007 को निर्णायक समीक्षा शुरूआत संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। घरेलू उद्योग से अक्टूबर, 2006 से सितम्बर, 2007 की जाँच अवधि के अनुसार संशोधित याचिका प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था क्योंकि पाटन एवं क्षति सुनिश्चित करने के लिए जांच अवधि हेतु प्रस्तुत किए गए आंकड़े पिछले तीन वर्षों के अतिरिक्त छह माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। राजस्व विभाग से भी दिनांक 1 जनवरी, 2008 से अनंतिम आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों को अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। राजस्व विभाग ने तदनुसार अपने दिनांक 27 दिसंबर, 2007 के पत्र के जरिए अपने कार्यालयों को निदेश दिया था। अतः, माननीय न्यायालय के दिनांक 1.11.2007 के आदेशों को समय पर कार्यान्वित किया गया था।

11. घरेलू उद्योग ने निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की थी और दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने के लिए उसने दो सप्ताह के समय विस्तार का अनुरोध किया था। एक निर्यातक ने भी तीन सप्ताह के समय हेतु अनुरोध किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और निर्यातक दोनों के लिए समय विस्तार को अनुमोदित किया था। घरेलू उद्योग को दिए गए समय विस्तार के बावजूद उन्होंने अब तक संगत सूचना/संशोधित याचिका प्रस्तुत नहीं की थी और उनके लिए बढ़ी हुई अवधि 25 फरवरी, 2008 को समाप्त हो गई। निर्यातक मै. चेल्याबिन्स्क इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल इंटिग्रेटेड प्लांट, जाइंट स्टॉक कं., रूस को सूचना प्रस्तुत करने हेतु दिया गया अतिरिक्त समय 3 मार्च, 2008 को समाप्त हो गया। तथापि, उनके प्रतिनिधि मै. स्ट्रैटेजिक मेटल्स प्रा. लि., मुम्बई ने निर्यातक प्रश्नावली में सूचना प्रस्तुत की थी जो विस्तार के समाप्त होने की तारीख अर्थात् 14.03.2008 को प्राप्त हुई थी। यह सूचना अपूर्ण थी क्योंकि इसमें घरेलू एवं निर्यात बिक्री से संबंधित परिशिष्ट I तथा II के संबंध में सूचना नहीं दी गई थी। उपर्युक्त के अलावा, आयातकों या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

12. घरेलू उद्योग से किसी सहयोग या सूचना के अभाव में घरेलू उद्योग द्वारा पाटन एवं क्षति के पुनः प्रारंभ होने का कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना अपेक्षित हो।

13. उपर्युक्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क, जो कि 25 दिसंबर, 2005 को समाप्त हो चुका है, को उसके अधिरोपण के 5 वर्षों के बाद जारी रखने की सिफारिश नहीं करते हैं। तदनुसार, चूंकि घरेलू उद्योग से पाटन एवं क्षति जारी रहने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है,

प्राधिकारी एतद्वारा दिनांक 01.01.2008 से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के अन्तिम आकलन को वापस लिए जाने की सिफारिश करते हैं।

14. इस सिफारिश पर आधारित केंद्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2008

FINAL FINDINGS

Subject : Sunset Review of Anti-dumping Investigations concerning imports of Ferro Silicon originating in or exported from Russia and China PR.

No. 15/19/2005-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, initiated a Sunset Review investigation vide notification dated 24.12.2007 into the alleged dumping of imports of Ferro Silicon from Russia and China PR. The Sunset Review investigation was initiated on the directions of Hon'ble High Court of Delhi, vide judgement dated 1.11.2007 in respect of petition filed by Domestic Industry, M/s Indian Metals & Ferro Alloys Ltd., Bhubaneswar.

2. The background of this case is that the Designated Authority under Rule 5 of the Rules, decided to initiate an anti dumping investigations concerning the import of Ferro Silicon originating in or exported from Russia and China PR. Consequently, an Initiation Notification dated 5th June, 2000 was issued to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported into India from the subject countries. On preliminary investigation, the Authority issued a public notice dated 16th Nov., 2000 vide Notification No.28/1/2000—DGAD where provisional duty was imposed on import of subject goods from subject countries. The provisional anti dumping duty was imposed on the subject goods vide Notification No.152/2000-Customs dated 26th December, 2000. The Designated Authority came out with final findings on 28th May, 2001 and recommended anti dumping duty as the difference between US \$ 764 and the landed value of import per metric tonnes (as mentioned in Column 3 of Para 9 of final findings). The definitive anti dumping duty was imposed by the Govt. of India vide Notification No.67/2001- Customs dated 25th June 2001. The anti dumping duty was applicable for a period of five years from the date of imposition of the provisional duty. The duty was, therefore, applicable upto 25th December, 2005.

145245/08-2

3. On completion of 4 years of the anti dumping duty imposed, an alert letter was sent to the Domestic Industry stating that the Designated Authority is contemplating to undertake Sunset Review under Section 9A(5) of Customs Act with a view to ascertain whether the cessation of the anti dumping duty in this case is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and they were requested to give full information regarding extent of imports from subject countries and evidence relating to dumping, if any, and impact of cessation of the anti dumping duty in this case.
4. The Domestic Industry (M/s. Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. and M/s. VBC Ferro Alloys) then filed the application for initiation of sunset review on the above subject. The matter was examined and after detailed examination, it was considered appropriate not to review the anti dumping duty imposed on Ferro Silicon on import from subject countries. The applicant was informed vide DGAD's letter dated 21.12.2005 accordingly.
5. Aggrieved by the letter dated 21st December, 2005, the applicant preferred a writ petition CW No.24646 of 2005 in Hon'ble High Court of Delhi and it was prayed that the Order dated 21.12.2005 may be quashed, since the Designated Authority is obliged to conduct a Sunset Review and the Central Government can then take a decision thereon. The Hon'ble Court ordered the Central Government to consider the matter and examine the correctness of the order passed by the Designated Authority.
6. This matter was considered by the Central Government (Department of Revenue) in pursuance of Hon'ble High Court's order and examined the correctness of the order passed by the Designated Authority. The decision of the Central Government was communicated vide letter dated 20th July, 2006. It was concluded that the Designated Authority's earlier decision not to review the anti dumping duty is well-founded and there exist no grounds to take a contrary view. It was, therefore, decided by the Government that a review for continuance of anti dumping duty on imports of Ferro Silicon from Russia and China PR is not required.
7. The petitioner again filed a writ petition on 13th November, 2006 vide – WP(C) No.16893/2006 in Hon'ble High Court of Delhi praying for setting aside the Order dated 20th July, 2006.

The Hon'ble Court in their Judgement dated 1.11.2007 held that:

- (a) A Sunset Review is mandatory and the contention of the Respondents to the contrary is rejected.
- (b) A Sunset Review is required to be conducted in accordance with procedure laid down in Rule 23 of the Rules.
- (c) The Order dated 20th July, 2006 passed by the Central Government is liable to be quashed and we do so.

As a result of above conclusion and relief granted, the Hon'ble Court directed to reconsider the request of the petitioner for Sunset Review in accordance with Rule 23 of Rules. The Hon'ble Court did not lay down any timeframe for the Respondents to take a decision but would, naturally, expect them to do so expeditiously.

8. The Hon'ble Court has also directed that with effect from two months after the date of decision (that is from 1st January, 2008) the Government will ensure that all imports of Ferro Silicon originating in or exported from Russia and China PR are cleared on a provisional basis till the Sunset Review is completed by the respondents and a final decision taken.

9. According to Sub Rule (2) of the Rules 6 Supra, the Authority forwarded a copy of the Initiation Notification dated 24.12.2007 for Sunset Review to the known producers/exporters, importers, industry associates, embassies of the countries concerned and the petitioner and gave them an opportunity to make their views known in writing. Copies of Initiation Notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM, etc. for wider circulation.

a) The Authority sent questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters from subject countries:

- i) China Hantonind. Ltd Jiangsu – China
- ii) Nanjing No. 3 Ferro-Alloy Plant, Jiangsu
- iii) Tianjing Non-Ferrous Metals – China
- iv) Hunau Ferro Alloy Plant – China
- v) Jinchuan Nono Ferrous Metals Co. – China
- vi) Jinzhou Ferro Alloys Plant – China
- vii) Nanjing Ferro Alloys Plant – China
- viii) Xiber Ferro Alloys Works Gansce – China
- ix) Xinyu Iron & Steel Works – China
- x) Xishui Country Ferro Silicon Plant, Hubei – China
- xi) Zunyi Ferro Alloy Plant Guizhou Province – China
- xii) Chelyabinsk Electro Metallurgical Integrated Plant – Russia
- xiii) Klutchersk Ferro Plant – Russia

b) A copy of Initiation Notification alongwith the importers questionnaire were also sent to the following importers:

- i) OPRK Ferro Alloys Ltd., New Delhi
- ii) ESSEL Mining and Industries Ltd., Kolkata
- iii) Metallic Alloys, New Delhi.
- iv) Durga Chemical Agency, Ludhiana.
- v) Himani Ferro Alloys Ltd., New Delhi.
- vi) British Metal Corpn (I), Pvt. Ltd.,
- vii) Metco Marketing India Pvt. Ltd., New Delhi.
- viii) Oswal Minerals, Bangalore.
- ix) Manohar Manak Alloy Pvt. Ltd., Mumbai.
- x) Sri Ram Enterprises, Chennai.
- xi) Sterling Ferro Alloys Pvt. Ltd., Vadodra
- xii) Kothari Metals, Ltd., Kolkata
- xiii) Sri Laxmi Traders Alloy, Bangalore

10. The Sunset Review Initiation Notification dated 24.12.07 was issued with a request to all concerned, i.e. Domestic Industry, exporters and importers etc. to furnish relevant information in the prescribed questionnaire within 40 days from the date of issue of letter dated 2.01.2008 as per normal procedure. The Domestic Industry was also requested to submit the revised petition as per period of Investigation from October, 2006 to September, 2007 as the data provided for the POI should not be older than 6 months besides 3 previous years to ascertain dumping and injury. The Department of Revenue was also requested to clear all imports of subject goods from subject countries on provisional basis w.e.f. 1st Jan., 2008. The Department of Revenue directed their offices accordingly vide their letter dated 27th December, 2007. The orders of the Hon'ble Court dated 1.11.07 was, therefore, implemented within the time frame.

11. The Domestic Industry did not submit information within the stipulated time and requested two weeks extension for submission of documents/information. One of the exporter also requested extension of three weeks. The Designated Authority approved the extension for both the Domestic Industry as well as exporter. In spite of extension given to Domestic Industry, they did not submit the relevant information/revised petition so far and the extension period expired on 25th Feb., 2008. The extension for submission of information by the exporter M/s Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Joint Stock company, Russia expired on 3rd March, 2008. However, their representative M/s Strategic Metals Pvt. Ltd., Mumbai submitted information on exporters questionnaire which was received on 14.03.08 i.e. after the due date of extension. This information was incomplete as it did not contain information on Appendix I and II pertaining to domestic and exports sale. Besides above, no response has been received either from the importers or any other interested party.

12. In the absence of any cooperation and information from the domestic industry, no case for continuation of dumping and injury to the domestic industry or likelihood of recurrence of dumping and injury has been made out by the domestic industry requiring continued imposition of anti dumping duty in terms of Sec 9A(5) of the Acts.

13. In view of the above findings, the Authority, does not recommend the continuation of anti dumping duty which had already expired on 25th Dec., 2005 after 5 years of its imposition. Consequently, as no material information for continued dumping and injury have been received from domestic industry, the Authority hereby recommend the withdrawal of provisional assessment of import of subject goods from subject countries w.e.f. 01.01.2008.

14. Any appeal against the Orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority